



पुणे महापालिका चुनाव: MNS ने आवेदन वितरण शुरू किया



पुणे — आगामी पुणे महापालिका चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने अपने उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्रों का वितरण शुरू कर दिया है। इससे पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को गति मिली है। मनसे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और कई कार्यकर्ताओं ने आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं।

इस बीच, पुणे महापालिका की स्थायी समिति की बैठक में शहर के विकास के लिए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जिससे शहर के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली | MGNREGA का नाम बदला —

MGNREGA का नाम बदला — अब 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना', रोजगार के लाभ भी बढ़ें

नई दिल्ली | — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का नाम बदलकर अब इसे “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना” कर देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से योजना को एक नई पहचान मिली है और इसके तहत लाभ भी बढ़ाए गए हैं।

सरकार के फैसले के अनुसार, अब ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिनों की कामगार



गारंटी की बजाय 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस योजना के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी को भी बढ़ाया गया है, जो लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहारा प्रदान करेगा। यह योजना 2005 में शुरू

की गई थी और तब से यह ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय स्तर पर संरचनात्मक विकास कार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब नाम बदलने के साथ ही योजना को और अधिक सुदृढ़ और लाभकारी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसका उद्देश्य न केवल महात्मा गांधी के आदर्शों को सम्मान देना है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और अधिक व्यापक तथा प्रभावी बनाना भी है। इस नई पहचान से लगभग 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, योजना का नाम बदलना और रोजगार तथा मजदूरी दिनों में वृद्धि करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा तथा विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।



उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष — बोले 'गुलामों' ने प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए!

नागपुर — विधानसभा के हिवाळी अधिवेशन के बीच मविआचे नेता और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखी कटाक्ष किए हैं। नागपुर में दूसरे दिन विधान परिषद में उपस्थित रहने के बाद मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने शिंदे की पहले की 'अराइवल' टिप्पणी को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। शिंदे ने उद्धव की विधानसभा हाज़िरी पर मज़ाक करते हुए 'आगमन' जैसा शब्द

इस्तेमाल किया था, जिसे राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय माना जा रहा है। मीडिया से बात में ठाकरे ने कहा कि “गुलामाने प्रतिक्रिया छायची नसते, आणि गांडुळाने फणा काढण्याचा प्रयत्न करायचा नसतो” — यानी गुलाम जैसी प्रतिक्रिया और पृथ्वी की केंचुए जैसा दिखना ठीक नहीं है, यह किसी को समझाना चाहिए। उन्होंने सीधे नाम लिए बिना शिंदे को निशाना बनाया, जिससे राजनीतिक माहौल और

गरमा गया है। ठाकरे और शिंदे के बीच शिवसेना के विभाजन के बाद से ही तनाव बना हुआ है। न्यायालयीन लड़ाई, पक्ष चिह्न विवाद और एक-दूसरे पर कटाक्ष लगातार जारी हैं। ठाकरे की इस तीखी टिप्पणी के बाद अब यह देखना बाकी है कि शिंदे गुट या उपमुख्यमंत्री की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हिवाळी अधिवेशन में यह विवाद और अधिक बढ़ सकता है।

नांदेड को बड़ी सौगात: 15 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी,



नांदेड को बड़ी सौगात: 15 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी, विधायक बालाजी कल्याणकर की मांग सफल

नांदेड नगर निगम की महत्वाकांक्षी 15 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। नांदेड उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालाजी कल्याणकर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग उठाई थी। उनकी पहल के बाद उपमुख्यमंत्री ने इस परियोजना को तुरंत शुरू करने की अनुमति प्रदान की।

लगभग 73.63 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना नगर निगम के बोंडार स्थित एसटीपी परिसर की उपलब्ध भूमि पर स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार की उस नीति के अंतर्गत इसे मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य नगर निकायों के बिजली खर्च को कम करने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। विधायक कल्याणकर ने बताया कि यह कदम नांदेड नगर निगम को बिजली के मामले में अधिक आत्मनिर्भर

बनाएगा और नागरिकों के लिए अन्य सुविधाओं के विकास में भी सहायक होगा। परियोजना शुरू होने पर प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 17 लाख 50 हजार यूनिट सौर बिजली उत्पादन की उम्मीद है। वर्तमान बिजली दरों के अनुसार नगर निगम को हर वर्ष करीब 16 करोड़ 87 लाख रुपये की बचत होगी। यह बचत जलापूर्ति, जलशोधन और सीवरेज शोधन केंद्रों के संचालन को और अधिक किफायती बनाएगी।



बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा — बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान की सुरक्षा क्यों घटाई?

मुंबई — बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कड़ी नाराज़गी जताते हुए पूर्व विधायक और नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा कम करने का आदेश वापस लेने और उसके पीछे के कारणों पर विस्तृत जवाब मांगा है। यह मामला तब उठा जब बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहज़ीन सिद्दीकी ने अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा में कमी के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने पूछा कि सुरक्षा घटाने के फैसले से पहले श्रेट पर्सप्शन कमिटी (टीपीसी) की बैठक कब और कैसे हुई, इसके मीटिंग मिनट्स (कार्यक्षेत्र) क्यों पेश नहीं किए गए।

हाईकोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की कि सुरक्षा कम किए जाने के फैसले में “प्रथम दृष्टया दुर्भावना की गंध” प्रतीत होती है और स्पष्ट कारण दिए बिना सुरक्षा हटाना गंभीर चिंता का विषय है। य+ स्तर की सुरक्षा पहले अधिक रही थी,

लेकिन अब केवल दो पुलिस कांस्टेबल ही तैनात हैं, जिससे सुरक्षा में कमी आई है। अदालत ने सरकार से इस निर्णय से जुड़े दस्तावेज और तर्क पेश करने को कहा है। शहज़ीन की याचिका में आरोप है कि उनके पति की हत्या के बाद भी सुरक्षा कम कर दी गई, जबकि जीशान पर संभावित खतरे का आरोप लगाए गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को बाबा के बेटे जीशान के बांदा कार्यालय के बाहर गोलीबारी में हुई थी, जिसे लेकर सुरक्षा की आवश्यकता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी है और महाधिवक्ता को पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला सुरक्षा व्यवस्थाओं, सरकारी निर्णय प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन की बड़ी बहस को जन्म दे रहा है।

नागपुर में कोट्यवधी का धान्य घोटाला — सवाल उठे रेशन की कालाबाजारी और बड़ी रसद पहुंचने पर आरोप

नागपुर में कोट्यवधी का धान्य घोटाला

NAGPUR

नागपुर — लोकमत की खबर के अनुसार नागपुर में कोट्यवधी रुपये मूल्य के रेशन धान्य घोटाले को लेकर गंभीर शंकाएं उठ रही हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच चर्चा है कि क्या धान्य की कालाबाजारी और घोटाले को दबाया गया है, क्योंकि कथित तौर पर माफियाओं को बड़ी रसद अवैध रूप से मुहैया कराई गई थी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और धंधेबाजों को सुरक्षित रह पाने का मौका मिला।

नेटवर्क से सुरक्षात्मक स्थिति बना ली है। घोटाले की तह तक जाने पर पता चला कि रेशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों के कारण गरीब और निराधार लोगों के हिस्से का धान्य कालाबाजार में चला जाता है। महीनेभर में 1300 से 1500 क्विंटल धान्य गायब हो जाने के आरोप थे, जिससे करोड़ों रुपये का अनाज खुले बाजार में बिकने की चर्चाएं सामान्य हो गई थीं।

सरकार के हिवाळी अधिवेशन के दौरान यह मामला प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान विधानसभा में भ्रष्टाचार, घोटाले और अन्याय जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस होती है। जबकि प्रशासन ने रेशन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई का आश्वासन दिया था, घोटाले की सच्चाई अब भी जारी है और कई लोगों का मानना है कि माफियाओं ने अपनी साख और रसद

पुलिस ने छापेमारी की और माफियाओं और कुछ कर्मचारियों में खलबली मची थी, लेकिन उसके बावजूद कालाबाजारी और रसद पहुंचने के सवाल अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस गट नेता विजय वडेटीवार ने इस गंभीर मामले को विधानसभा में उठाया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब तक प्रशासन की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या घोटाले को दबाया जा रहा है या नहीं।



पुणे में अवैध उत्खनन मामला: 10 महसूल अधिकारियों को निलंबित, 90,000 ब्रास खनिज के अवैध उत्खनन का खुलासा

पुणे में अवैध उत्खनन मामला: 10 महसूल अधिकारियों को निलंबित, 90,000 ब्रास खनिज के अवैध उत्खनन का खुलासा

पुणे — महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले के मावळ तालुका में डॉंगरों के अवैध उत्खनन मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 महसूल अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लिया और इसकी सूचना सदन को दी। सरकारी जांच में यह खुलासा हुआ कि मंगरूळ क्षेत्र में कंत्राटदार को कुल 3,63,000 ब्रास उत्खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन 4,54,000 ब्रास से भी अधिक उत्खनन किया गया था। यानी अनुमति से लगभग 90,000 ब्रास खनिज का अनधिकृत उत्खनन हुआ, जो गंभीर उल्लंघन

माना गया। इसके अलावा कुछ समूह स्थानों पर भी बिना अनुमति उत्खनन के सबूत मिले। विधानसभा में आमदार सुनील शेळके ने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों ने अटकल रिपोर्ट दी और कार्रवाई करने में महीनों तक देरी की, जिससे अवैध उत्खनन जारी रहा। इस गंभीर आरोप के बाद मंत्री बावनकुळे ने तत्काल कदम उठाने की घोषणा की। निलंबित अधिकारियों में 4 तहसीलदार (जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख), 4 मंडल अधिकारी (संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम) और 2 तलाठी (दीपाली सनगर,

गजानन सोटपल्लीवार) शामिल हैं। इन पर कर्तव्य में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल निलंबन ही पर्याप्त नहीं है। दोषियों के खिलाफ गुन्हे दर्ज किए जाएंगे, जुर्माना वसूला जाएगा, और यदि समय पर दंड नहीं भरा गया तो बोजा वसूल किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच तीन महीने के भीतर पूरी कर अगली विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ शासन की सख्त नीति को दर्शाती है और संकेत देती है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में कठोर निगरानी रखी जाएगी।

किसान संकट पर विधानसभा में हंगामा—MSP, खरीदी व्यवस्थाओं और सरकार-विपक्ष की जवाबदेही

संपादकीय |

महाराष्ट्र विधानसभे के नागपुर हिवाळी अधिवेशन में 12 दिसंबर का दिन पूरी तरह किसानों के मुद्दों पर छाया रहा। कपास और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की खरीदी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सदन में तीखा वाद-विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ी कि विपक्ष ने नारेबाजी के बीच वॉकआउट भी किया। यह दृश्य न तो नया है और न ही अप्रत्याशित, परंतु किसानों के सामने खड़ी वास्तविक चुनौतियों को देखते हुए यह प्रश्न फिर उभर कर सामने आता है—क्या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप किसानों के सवालों का समाधान बन सकते हैं?

विपक्ष का आरोप है कि कई खरीदी केंद्र ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। कपास और सोयाबीन की तौल, गन्नी बैग की उपलब्धता, भुगतान में देरी और MSP प्रक्रिया में अव्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। यह तथ्य है कि खरीफ सीज़न में किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं, उत्पादन लागत में भारी वृद्धि और बाज़ार में अस्थिरता से जूझते हैं। ऐसे में सरकारी खरीद केंद्र यदि समय पर काम न करें, या उनकी प्रक्रियाएँ धीमी पड़ जाएँ, तो स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो जाती है।

सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विभागीय स्तर पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सरकार ने विधानसभा में भारी भरकम पूरक बजट पेश किया, जिसका बड़ा हिस्सा कृषि-संबंधी योजनाओं और सहायता हेतु बताया गया है। आर्थिक सहायता निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सहायता केवल संख्या और घोषणाओं के माध्यम से किसानों तक पहुँच सकती है, या इसके लिए जमीनी स्तर पर एक मजबूत प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता है?

किसान संकट पर चर्चा का दूसरा पहलू यह है कि यह केवल MSP या खरीदी केंद्रों की समस्या नहीं है। यह पूरे कृषि प्रबंधन मॉडल की जटिलता से जुड़ा मुद्दा है। किसानों के लिए बाज़ार तक पहुँच, मूल्य स्थिरता, समय पर भुगतान, और फसल बीमा की पारदर्शी व्यवस्था—ये सभी कारक मिलकर राहत प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वर्षों से इन मुद्दों पर सतत सुधार का अभाव राजनीतिक बहसों में ढँक जाता है।

विधानसभा में उठाए गए सवालों को केवल विरोध का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज़ करना भी उचित नहीं होगा। विपक्ष का काम ही है कि वह सरकार की कमियों पर प्रकाश डाले। लेकिन विपक्ष की आलोचना तब सार्थक होती है जब वह समाधान की दिशा भी प्रस्तुत करे। किसानों के संयुक्त रणनीति शायद यह दिखा सकती है कि वे किसानों के प्रति एकजुट होकर गंभीर हैं। दुर्भाग्य से आज की राजनीति में ऐसा सामूहिक दृष्टिकोण दिखना दुर्लभ होता जा रहा है।

दूसरी ओर, सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह विपक्ष की आलोचना को केवल राजनीतिक हमला मानकर खारिज न करे। MSP की वास्तविक पहुँच, खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, भुगतान की समयबद्धता और किसानों की शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक मजबूत बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसान सड़कों पर प्रदर्शन करें, या सदन में लगातार हलचल बनी रहे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि जमीन पर समस्याएँ वास्तविक हैं और उनका समाधान केवल बयानबाजी से संभव नहीं है।

इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण सीख यह भी है कि किसान मुद्दा अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। यह सकारात्मक पहलू है, क्योंकि किसानों की आकांक्षाओं और कठिनाइयों पर चर्चा होना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। लेकिन चर्चा तभी प्रभावी मानी जाएगी जब उसके परिणाम जमीन पर दिखाई दें।

अंततः, सदन का कर्तव्य है कि वह इस विषय पर शोर नहीं, समाधान पैदा करे। किसानों की चिंताएँ केवल किसानों की नहीं, बल्कि राज्य और देश की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ी हैं। यदि किसान सुरक्षित नहीं, तो कृषि सुरक्षित नहीं—और यदि कृषि सुरक्षित नहीं, तो अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित नहीं रह सकती। यही कारण है कि किसानों के मुद्दों पर सदन में हुआ यह हंगामा केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

BUSINESS| सर्विसेज जैसे वाला इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में सक्षम किया है।

₹34,000 करोड़ की इनकम, ₹7,588 करोड़ का प्रॉफिट... बिकने जा रहा है यह सरकारी बैंक!

● Reporter Name

नई दिल्ली: आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में टोरंटो की फेयरफैक्स फाइनेंशियल सबसे आगे चल रही है। वित्तीय बोली जमा करने की आखिरी तारीख दिसंबर के अंत तक है। इस बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। फेयरफैक्स फाइनेंशियल के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक भी आईडीबीआई बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की होड़ में है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंक की इनकम 34,000 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 7,588 करोड़ रुपये रहा।

फेयरफैक्स फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा बैंक ने दो साल पहले आईडीबीआई में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। फेयरफैक्स फाइनेंशियल की स्थापना भारतीय मूल के कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स ने की थी।



आईडीबीआई बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से पूरी तरह ऑल-कैश ऑफर देने पर विचार कर रही है। इस वजह से फेयरफैक्स फाइनेंशियल बोली प्रक्रिया में पसंदीदा बन सकती है।

स्टेक की कीमत कितनी है? भारत सरकार और एलआईसी

मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से यह हिस्सेदारी करीब 7 अरब डॉलर की है। आईडीबीआई बैंक के शेयर इस साल अब तक लगभग एक चौथाई चढ़े हैं। बैंक का बाजार मूल्य 1.02 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक कैश और शेयर

कंभिनेशन के साथ बोली लगाने पर विचार कर रहा है। जानकारों का कहना है कि बोलियां जमा करने की प्रक्रिया जनवरी की शुरुआत तक खिंच सकती है।

एमिरेट्स एनबीडी ने भी आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी।

लेकिन अब वह अपनी भागीदारी पर फिर से विचार कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हाल ही में आरबीएल बैंक (RBL Bank) में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है।

फेयरफैक्स फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा बैंक ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एमिरेट्स एनबीडी ने संपर्क करने पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

शेयर की चाल सरकार ने तीन साल पहले आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की मंशा जताई थी। उसके बाद से बैंक को शेयरों में तीन गुना तेजी आ चुकी है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर करीब 3 फीसदी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 11.48 बजे बीएसई पर यह 2.84% तेजी के साथ 97.85 रुपये था। इसके साथ ही इसका मार्केट कैप 1,05,212.26 रुपये पहुंच गया।

Business- इंडिगो को मिला 58 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस,

इंडिगो को मिला 58 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, 4 इंस्पेक्टर टर्मिनेट, आज भी 54 फ्लाइट कैंसिल

कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हाल में कंपनी के कामकाज में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। इस कारण हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी इंडिगो की 54 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं।

इंडिगो भारत में करीब 65% से ज्यादा घरेलू उड़ानों का संचालन करती है। पिछले 10 दिनों में इस एयरलाइन ने हजारों फ्लाइट कैंसिल की हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब 1 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FTDL) के नए नियम लागू हुए। लेकिन 2 दिसंबर से हालात बेकाबू हो गए। इन नियमों के तहत, पायलटों और कू

र्म्बर्स को ज्यादा आराम मिलेगा। रात की ड्यूटी कम होगी और हफ्ते में 48 घंटे का आराम जरूरी होगा।

. चार FOI टर्मिनेट नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का बादा किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी एयरलाइन कोयात्रियों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को टर्मिनेट कर दिया है। इन लोगों को एयरलाइन की सेफ्टी और ऑपरेशन कंप्लायंस की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

₹1,00,000 करोड़ की बंपर कमाई... भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस साल प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और अन्य शुरुआती निवेशकों ने आईपीओ के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। अब तक आए 102 आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 1.76 लाख करोड़ जुटाए हैं। इसमें से 63% यानी 1.11 लाख करोड़ रुपये उन शेयरधारकों के हिस्से में आए हैं जिन्होंने ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेची है। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक पिछले साल यह आंकड़ा 95,000 करोड़ रुपये था। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2020 में यह सबसे अधिक 86.7% था।

निवेशकों की बाहर निकलने की सबसे ज्यादा होड़ खासकर नए दौरे की टेक्नोलॉजी कंपनियों और बड़े IPO में

देखी गई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 11,607 करोड़ रुपये का IPO पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था। टाटा कैपिटल के 15,500 करोड़ रुपये के बड़े IPO में 8,600 करोड़ रुपये से ज्यादा OFS के जरिए आए। ICICI प्रूडेंशियल AMC का 10,600 करोड़ रुपये का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। यह पूरी तरह से OFS है।

ट्रेंड से बढ़ी चिंता Lenskart के 7,278 करोड़ रुपये के IPO में 5,127 करोड़ रुपये मौजूदा निवेशकों के पास गए, जो कि 70% OFS था। Groww के पब्लिक डेब्यू में 5,572 करोड़ रुपये OFS के जरिए आए, जो कि ज्यादातर हिस्सा था। HDB फाइनेंशियल के 12,500 करोड़ रुपये के ड्रश्य में 10,000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बिक्री

शामिल थी, जबकि NSDL का 4,010 करोड़ रुपये का IPO पूरी तरह से बिकवाली थी।

इस ट्रेंड से यह चिंता पैदा हुई है कि PE फंड ऊंचे दामों पर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं, जबकि रिटेल निवेशक इसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि यह आलोचना गलत है। उनका तर्क है कि मौजूदा बाजार की स्थितियां उन्हें बाहर निकलने का एक तर्कसंगत मौका दे रही हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, "हम PE निवेशकों से सही मूल्यांकन पर बेचने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक सीधा व्यापार प्रस्ताव है।"

चीन-जापान तनाव का समाधान जल्द नहीं, ताइवान बयान और कूटनीतिक दबाव वजह

टोक्यो/बीजिंग — चीन और जापान के बीच चल रहा तनाव इस बार आसानी से समाप्त नहीं होने के संकेत दे रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। यह विवाद जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची द्वारा ताइवान को लेकर दिए गए बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो जापान को मिलिटरी हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलेगा। इससे बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और राजनयिक संकट और गहरा गया।

चीन ने जापान के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाया, जिसमें जापानी समुद्री भोजन और अन्य वस्तुओं के आयात पर रोक तथा सामाजिक-आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा बीजिंग ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की मानसिकता से बाहर निकलने की चेतावनी दी है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विश्वासहीनता और बढ़ी है।

चीन-जापान तनाव का समाधान जल्द नहीं



चीन ने जापान के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाया, जिसमें जापानी समुद्री भोजन और अन्य वस्तुओं के आयात पर रोक तथा सामाजिक-आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा बीजिंग ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की मानसिकता से बाहर निकलने की चेतावनी दी है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विश्वासहीनता और बढ़ी है।

बीजिंग और टोक्यो के बीच कूटनीतिक चैनल भी सीमित होते जा रहे हैं और विवादित मुद्दों पर कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐतिहासिक मतभेद, सुरक्षा चिंताएं और ताइवान को लेकर प्रत्यक्ष विरोधाभास तनाव को और लंबा खींच सकते हैं।

चीन और जापान एशिया-प्रशांत क्षेत्र की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं और उनके बीच तनाव का प्रभाव व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय शांति पर भी पड़ा है। इस कारण वर्तमान विवाद का जल्द समाधान होने की संभावना कम दिखाई देती है।

ट्रंप का नया “कोर-5” प्लान: यूरोप और NATO से दूरी, भारत-चीन-रूस-जापान को साथ लाने की तैयारी

वॉशिंगटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए वैश्विक मंच “कोर-5” (C5) सुपरक्लब पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया की प्रमुख महाशक्तियों — अमेरिका, भारत, चीन, रूस और जापान — को एक साथ लाने का लक्ष्य रखता है। यह प्रस्ताव परंपरागत पश्चिमी समूह G7 का विकल्प माना जा रहा है, जिससे यूरोप और NATO से दूरी भी स्पष्ट होती है। ट्रंप का मानना है कि पुराने गठबंधनों में अब अमेरिका की प्राथमिकताओं का पूरा समर्थन नहीं मिलता और वैश्विक शक्तियों के बीच नया संतुलन जरूरी है। ‘कोर-5’ को G7 के



समान समिट-आधारित सहयोग मंच के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा-संबंधी मुद्दों पर नियमित बैठकों और समन्वय की योजना है। ट्रंप ने कहा है कि यदि रूस और चीन जैसे देशों को इस मंच में शामिल किया जाता, तो शायद यूक्रेन युद्ध जैसी स्थिति पैदा न

होती। इसी विचार से यह नई पहल उजागर हुई है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप इस समूह को बनाकर न सिर्फ वैश्विक राजनयिक संबंधों को स्थिर करना चाहते हैं, बल्कि मध्य पूर्व सुरक्षा, इजरायल-सऊदी अरब के बीच रिश्तों का संतुलन जैसे अहम मुद्दों को भी

सम्मिलित करना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों — यूरोपीय देशों और NATO — पर निर्भरता कम करते हुए बहुध्रुवीय राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ‘कोर-5’ के गठन से विश्व शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है और इससे NATO जैसे गठबंधनों की भूमिका पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। इसका प्रभाव वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक धुरी पर गहरा पड़ सकता है, जिससे नई रणनीतिक चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।

भारत ही नहीं, अब तालिबान से भी जंग लड़ेगा लश्कर-ए-तैयबा, अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर जहर उगला

इस्लामाबाद | पाकिस्तानी सेना के शागिर्द कुरख्वात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने बड़ा ऐलान किया है। लश्कर के एक सीनियर लीडर ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन में अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऑफर दिया है। लश्कर आतंकी ने पाकिस्तान पर हो रहे हमलों को लेकर तालिबान को सख्त चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल असीम मुनीर का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया है। यह बहुत दुर्लभ मौका है, जब लश्कर-ए-तैयबा ने खुलेआम पाकिस्तानी सेना और उसके अजीमोशान शहंशाह असीम मुनीर का इतने खुले तौर पर समर्थन किया है।

भारत के बाहर दायरा बढ़ा रहा लश्कर

तालिबान को धमकी और असीम मुनीर का समर्थन लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद का करीबी और आतंक की दुनिया का जाना-माना चेहरा कारी याकूब शेख ने किया है। उसने एक वीडियो मैसेज में यह बात कही है, जो कि पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों के लिए एक दुर्लभ घटना है। इससे पहले तक यह आतंकी संगठन भारत विरोधी ऑपरेशन पर फोकस करता रहा है। यह पहली बार है, जब लश्कर के किसी सीनियर नेता ने इतने खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया है और देश के दूसरे छोर पर जारी तनाव को लेकर तालिबान को धमकी दी है।



पाकिस्तानी सेना और मुनीर की तारीफ

वीडियो मैसेज में लश्कर आतंकी कारी याकूब शेख ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ की है और इस्लामिक भाईचारे की अपील की गई है। उसने सीमा पार अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी है। शेख ने जनरल आसिम मुनीर के हाल के स्ट्रेटेजिक

फैसलों का जोरदार समर्थन करते हुए अपने बयान की शुरुआत की। उसने कहा कि इन कदमों से देश के धार्मिक मौलवियों के बीच “भरोसा और सम्मान” बढ़ाने में मदद मिली है। उसने पाकिस्तानी मौलवी और मौलानाओं की भी देश की सुरक्षा में भागीदारी और तालिबान पर दबाव बनाने में उन्हें इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी सेना की रणनीति की तारीफ की।

लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ नेता कारी याकूब शेख ने पाकिस्तानी सेना और जनरल असीम मुनीर का खुलेआम समर्थन किया है। उन्होंने अफगान तालिबान को चेतावनी दी है कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर हमले न हों, अन्यथा लश्कर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ेगा।

तालिबान को जंग की धमकी

शेख ने अफगान तालिबान से कहा कि वे साफ तौर पर, सबके सामने यह ऐलान करें कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर कभी कोई हमला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अफगान तालिबान की तरफ से यह ऐलान होना चाहिए कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी।" उसने चेतावनी दी: "अगर ऐसा भरोसा नहीं दिया जाता है, तो यह याद रखें: पाकिस्तान की रक्षा के लिए, हम पाकिस्तानी सेना के साथ मज़बूती से खड़े हैं।" इस धमकी का मतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा अफगानिस्तान के साथ संभावित टकराव में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हमला करने के लिए तैयार है।

तीन महीने में तीसरी बार... भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती तो देखें, पाकिस्तान को बड़ा झटका देगा तालिबान



अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद तीसरा मंत्री स्तरीय दौरा होगा। यह दौरा पाकिस्तान से घटिया दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध के बीच हो रहा है, जिससे भारत के साथ दवा आयात समझौते की उम्मीद है। भारत अफगानिस्तान को स्वास्थ्य सहायता जारी रखे हुए है।

काबुल: काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भी भारत-अफगानिस्तान संबंधों में तेजी देखी जा रही है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के शीर्ष मंत्री लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। यह पिछले 3 महीने में इस्लामिक अमीरात सरकार की तरफ से तीसरा मंत्री स्तरीय दौरा होगा। यह दौरा 17 दिसंबर के आसपास होने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री अमीर खा मुत्ताकी और नवंबर में व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने भारत का दौरा किया था। भारत-अफगानिस्तान संबंधों के मजबूत होने से पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है।

पाकिस्तान से दवाई आयात पर प्रतिबंध के बीच दौरा तालिबान शासित इस्लामिक अमीरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दौरा पाकिस्तान से दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद हो रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की दवाइयां घटिया हैं, जिनसे अफगान लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक अमीरात दवाइयों के आयात को लेकर भारत के साथ समझौता कर सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्वास्थ्य सहयोग पहले से ही काफी मजबूत है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान भी बड़े पैमाने पर मानवीय मदद जारी रखी है।

कर रहा भारत इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, भारत के दूत पी हरीश ने अफगानिस्तान को दी जा रही स्वास्थ्य सहायता पर जोर दिया, "भारत अफगान नागरिकों को मेडिकल मदद और अच्छी क्वालिटी का हेल्थकेयर इलाज देना भी जारी रखे हुए है।" उन्होंने आगे कहा कि "अफगान पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के आने वाले भारत दौरे के दौरान हेल्थकेयर सहयोग को और बढ़ाया जाएगा।" मुत्ताकी के दौरे के दौरान, भारत ने 20 एम्बुलेंस तोहफे में दीं। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप आने पर भी तुरंत मदद की, खाना, राहत का सामान और शरणार्थियों के लिए मदद पहुंचाई।

अफगानिस्तान की कैसे मदद

ट्रंप प्रशासन का 'बर्थ टूरिज्म' पर बड़ा फैसला, गर्भवती महिलाओं को वीजा मिलने पर लटकी तलवार! जानें भारतीयों पर असर?

वॉशिंगटन: वीजा और इमिग्रेशन पर सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने उन महिलाओं को वीजा नहीं देने का फैसला लिया है, जो अमेरिकन नागरिकता पाने के लिए यहां आकर बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंसी के ऐसे वक्त में ट्रैवल वीजा मांगती है, जब अमेरिका में रहने के दौरान वह मां बन सकती है तो उसका वीजा कैंसिल किया जा सकता है। इस फैसले से भारतीय बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकते हैं।

बर्थ टूरिज्म' रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस ऐलान के बाद वीजा के लिए अप्लाई करने वाली शायदीशुदा या प्रेग्नेंट महिलाओं की जांच-पड़ताल बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासियों और वीजा के मामले में लगातार सख्त है।

बर्थ टूरिज्म और अमेरिका | अमेरिकी संविधान अमेरिका की धरती पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता देता है। यानी अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चों को ऑटोमैटिक नागरिकता मिल जाती है। इसी वजह से जब कुछ

'US कॉन्सुलर ऑफिसर टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन को मना कर देंगे अगर उन्हें लगता है कि ट्रैवल का मुख्य मकसद बच्चे के लिए सिर्फ US नागरिकता पाने के लिए बच्चे को जन्म देना है। इसकी किसी सूत्र में इजाजत नहीं दी जाएगी।'

बर्थ टूरिज्म पर ट्रंप की सख्ती अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार बर्थराइट सिटिजनशिप की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी अमेरिका आने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं की कड़ी निगरानी की बात कही गई थी। अब एक बार फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्थ टूरिज्म पर अपना सख्त रुख दिखाया है। ट्रंप प्रशासन ने उन आवेदकों को B-1/B-2 टूरिस्ट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है, जिन पर बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा करने का शक है। बर्जिन लॉ के सीनियर पार्टनर केतन मुखीजा ने कहा है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट दिख रही हैं, उन्हें अब वीजा पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में अमेरिका की एम्बेसी ने गुरुवार को इस संबंध में कड़ा बयान जारी किया है। एम्बेसी ने एक्स पर लिखा,



मराठवाड़ा में भारतीय मौसम विभाग का शीतलहर येलो अलर्ट, नागरिक रहें सतर्क



रिपोर्ट: मराठवाड़ा में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट आई है। भारतीय मौसम विभाग ने मराठवाड़ा के कई जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रात के तापमान में सामान्य से काफी कमी दर्ज की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 6°C तक गिर गया है, जिससे नागरिकों के लिए ठंड से प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।

मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की हिदायत दी है। उबदार कपड़े पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही, किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की जानकारी दी गई है। अगले दो-चार दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।

नई दिल्ली | महाराष्ट्र में तीन माह में 766 किसानों की आत्महत्या:

महाराष्ट्र में तीन माह में 766 किसानों की आत्महत्या: राहत पैकेज पर सवाल, राज्यसभा में गूंजा दर्द

नई दिल्ली | महाराष्ट्र की किसान आत्महत्या समस्या एक बार फिर संसद में बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई। राकांपा (शरद पवार गुट) की राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने गुरुवार को शून्यकाल में बताया कि पिछले तीन महीनों में राज्य में 766 किसानों ने आत्महत्या की, जो कृषि संकट की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया – “किसान सरकार के लिए कब प्रिय होंगे?”



सांसद खान ने कहा कि इस साल भारी बारिश, लगातार बाढ़ और फसलों को व्यापक नुकसान के बाद 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के पास महाराष्ट्र से अतिरिक्त सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है, जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में

कहा।

राहत राशि के वितरण पर भी सांसद ने नाराजगी जताई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत किसानों के लिए 4,176 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें कोष की 3,180 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी शामिल थी। इसके बावजूद 1,13,455 किसानों के खातों में मात्र 82 करोड़ रुपये ही जमा किए गए।

उन्होंने इसे “गरीब किसानों के साथ अन्याय” बताते हुए कहा कि यह आंकड़े चौंकाने वाले और बेहद निराशाजनक हैं।

फौजिया खान ने राज्य सरकार की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया था कि बाढ़ से 19 जिलों में 14.36 लाख हेक्टेयर भूभाग प्रभावित हुआ, लेकिन केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में केवल 1,10,309 हेक्टेयर नुकसान का उल्लेख किया गया। उन्होंने इसे किसानों के साथ “मजाक” और “क्रूर अन्याय” करार दिया।

सांसद ने सरकार से अपील की कि इस स्थिति को सामान्य मौसमी नुकसान न समझा जाए, बल्कि लाखों किसानों को प्रभावित करने वाली कृषि आपदा के रूप में गंभीरता से लिया जाए।



पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का निधन, राजनीति की एक युगपीठ ढही

लातूर (महाराष्ट्र), 12 दिसंबर 2025: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का आज सुबह अपने लातूर स्थित आवास देवघर में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने लंबी बीमारी के बाद आज सुबह अंतिम सांस ली।

राजनीति में उनके करियर को चार दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त था। वे महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर गांव के रहने वाले थे

और अपने समय में लोकसभा के स्पीकर तथा कई केंद्रीय पदों पर रह चुके थे। पाटिल ने 2004 से 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में सेवा दी और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा।

उनकी राजकीय यात्रा में उन्होंने • लोकसभा के 10वें स्पीकर के रूप में भी कार्य किया, • पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ प्रशासन के

प्रशासक के रूप में सेवा दी, • और कई केंद्रीय मंत्रालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया।

उनके निधन पर राजनीति, सामाजिक व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेताओं सहित महाराष्ट्र के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने शोक संदेश जारी किए हैं। परिवार में उनके बेटे शैलेश पाटिल, बहू अर्चना पाटिल (बीजेपी नेता) व दो पोतियाँ शामिल हैं, जो उनका दुःख साझा कर रहे हैं।



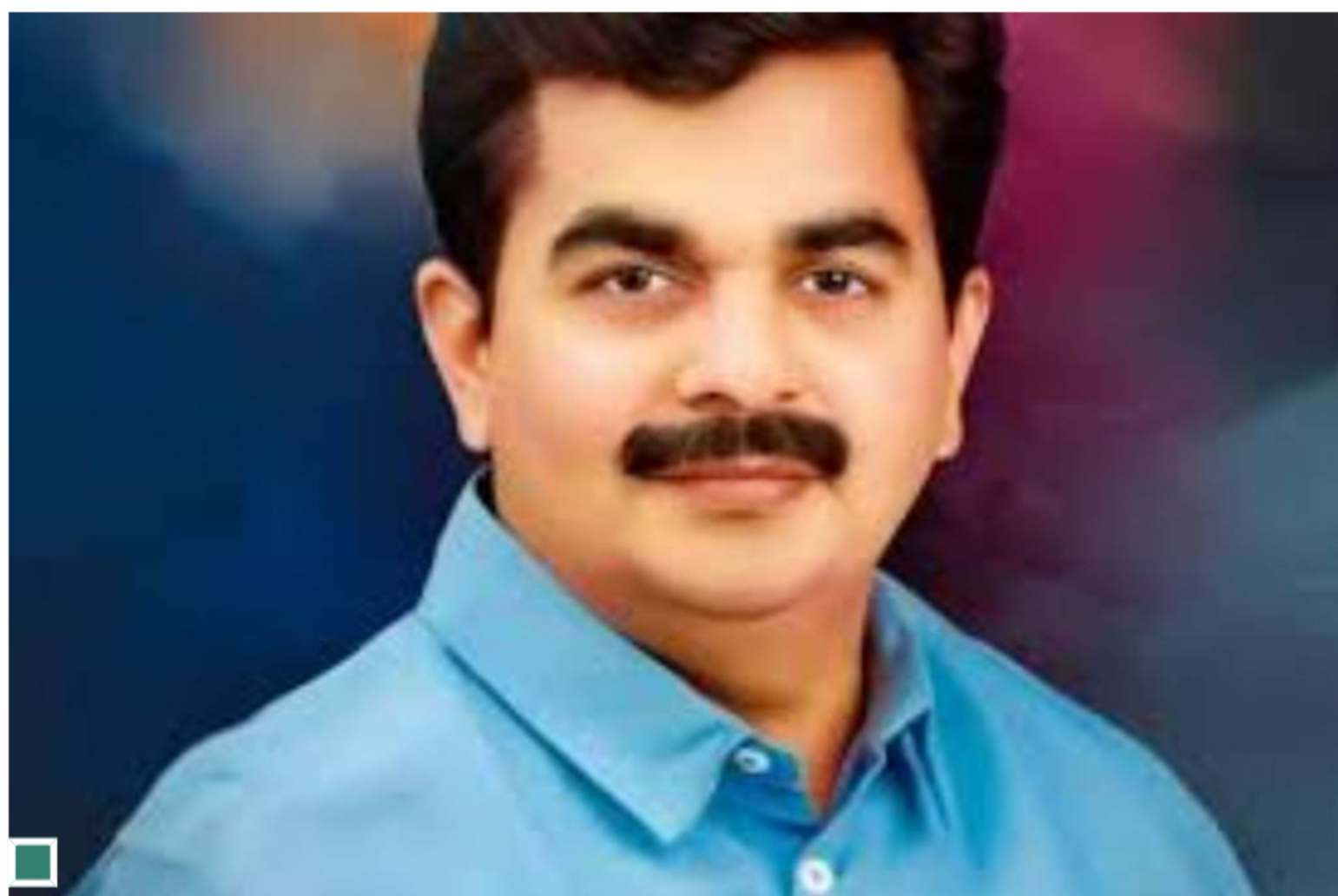
रेत माफियों पर दिखावटी कारवाई: प्रशासन का 'नूरा कुस्ती' खेल

नांदेड जिले में अवैध वाळू उपसा के खिलाफ प्रशासन की कारवाई अक्सर केवल दिखावटी साबित होती है। जैसे अखाड़े में दो पहलवान तय करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारे, वैसे ही प्रशासन अवैध रेत उपसा रोकने के लिए बोटों के खिलाफ ‘नूरा कुस्ती’ का नाटक करता है। बोटों को जब्त करने और भंगार बनाने की बजाय केवल इंजिनों को विस्फोट कर नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे बोटें जल्दी दुरुस्त होकर पुनः अवैध कार्य में लग जाती हैं।

जिल्हे के सभी नदी घाटों में अवैध रेत उपसा जारी है। जितने जिम्मेदार रेत माफिया हैं, उतने ही जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। महसूल और पुलिस प्रशासन यदि ईमानदारी से कर्तव्य निभाएँ तो अवैध उपसा पर पूरी तरह लगाम लग सकती है। बावजूद

इसके कई अधिकारी केवल कारवाई का दिखावा करते हैं, जिससे नदी पात्र में बोटें आसानी से फिर से अवैध रेत उठाने लगती हैं।

जलसंपदा विभाग और तहसीलदार स्तर के अधिकारी खुलेआम अवैध उपसा को नजरअंदाज करते हैं। साथ ही, राजकीय संरक्षण और स्थानीय नेताओं का दबाव इस अवैध धंधे को और मजबूत कर रहा है। जनमानस की मांग है कि प्रशासनिक दबाव और राजकीय संरक्षण को उजागर किया जाए, ताकि रेत माफिया पर वास्तविक नियंत्रण हो सके और दिखावटी कारवाई का पर्दाफाश हो। इस तरह, जिले में रेत माफियों पर की जा रही कारवाई वास्तव में ‘दिखावटी नूरा कुस्ती’ बनकर रह गई है, जिससे अवैध उपसा पर कोई ठोस रोक नहीं लग पा रही है।



महाराष्ट्र के सोयाबीन-कपास किसानों को तत्काल राहत दें: सांसद रवींद्र चव्हाण की लोकसभा में मांग

नांदेड के सांसद रवींद्र चव्हाण ने लोकसभा में महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों की गंभीर स्थिति उठाते हुए केंद्र सरकार से त्वरित राहत और न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि, खराब मौसम और गुणवत्ता में गिरावट के कारण किसान भारी नुकसान में हैं, जबकि व्यापारियों ने कृत्रिम रूप से दाम गिराकर संकट

और बढ़ा दिया।

चव्हाण ने नाफेड और सीसीआई की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई जगह खरीद केंद्र समय पर नहीं खुले, धीमी गति से काम हुआ और गलत सातबारा नॉड दिखाकर किसानों को लौटाया गया। उन्होंने नाफेड द्वारा डागदार सोयाबीन की सीमा 5% से घटाकर 3%

करने के निर्णय को किसान-विरोधी बताया।

उन्होंने यह भी पूछा कि कृत्रिम भावपतन के जिम्मेदार व्यापारी गुटों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। चव्हाण ने केंद्र से विशेष खरीद अभियान शुरू करने, नुकसान की भरपाई करने और किसानों को तत्काल न्याय देने की मांग की।



नांदेड में पत्रकार भवन निर्माण हेतु निधि मंजूर किया जाए: विधायक आनंदराव बोंडारकर की मांग

नांदेड दक्षिण के विधायक आनंदराव करने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होने बोंडारकर ने हिवाळी अधिवेशन के दौरान के बावजूद नांदेड में अब तक एक भी नांदेड में आधुनिक व सुसज्जित पत्रकार समर्पित पत्रकार भवन उपलब्ध नहीं है। भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त निधि मंजूर पत्रकार भवन के लिए आवश्यक 10 हजार करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि वर्गफुट भूमि सिडको के निकट स्थित है, नांदेड की पत्रकारिता लगभग 70 वर्षों की जहां हाल ही में अतिक्रमण हटाया गया है। गौरवशाली परंपरा लिए हुए है और जिले के उन्होंने मांग की कि इस स्थान पर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बहुमंजिला, सभी सुविधाओं से युक्त भवन व कृषि क्षेत्र के विकास में पत्रकारों का निर्माण हेतु सरकार तत्काल भरीव आर्थिक योगदान अतुलनीय रहा है। सहायता उपलब्ध कराए, जिससे जिले के पत्रकारों को एक सशक्त और व्यवस्थित कार्यस्थल मिल सके।

बोंडारकर ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत



नांदेड के इनामी जमीन धारकों के लिए बड़ी राहत: विधायक कल्याणकर की मांग पर महसूल मंत्री का आश्वासन

नांदेड: राज्य की हिवाळी अधिवेशन में नांदेड उत्तर विधानसभा क्षेत्र की भाडेपट्टे पर आधारित इनामी जमीनों के नियमितीकरण का मार्ग साफ हुआ है। नांदेड उत्तर के विधायक बालाजी कल्याणकर द्वारा उठाई गई मांग को राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सकारात्मक उत्तर देते हुए माना।

विधायक बालाजी कल्याणकर ने मौ. असदुल्लाबाद स्थित स.नं. 28, 29 और 42 की भाडेपट्टे पर आधारित इनामी जमीनों के मुद्दे को

विधानसभा में उठाया। उन्होंने मांग की कि इन जमीनों का नियमों के अनुसार पुनर्संरक्षण किया जाए और इससे प्रभावित धारकों को राहत दी जाए। साथ ही, भोगवटादार वर्ग-2 की जमीनों को वर्ग-1 में बदलने की सिफारिश की।

जमीनों की पुनर्मांटन (रिप्रांट) प्रक्रिया के दौरान सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना किए गए लेन-देन को शर्तभंग माना गया। इसके अलावा, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं द्वारा अकृषिक अनुमति और मंजूरी के आधार पर

रहिवासी भूखंडों का हस्तांतरण भी दूसरा बड़ा शर्तभंग बन गया, जिससे हजारों मालमत्ताधारक समस्याओं में फंस गए थे।

महसूल मंत्री बावनकुले ने आश्वासन दिया कि इन इनामी जमीनों को नियमित करने वाले विधेयक के अधिनियम में नांदेड की मांग को शामिल किया जाएगा। इस आश्वासन से नांदेड सहित राज्य के दीर्घकालीन भाडेपट्टे पर आधारित इनामी जमीनों के धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है।